राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 2 ■ अंक 6 ■ सितम्बर 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 28

Updating NRC NEED OF THE HOUR

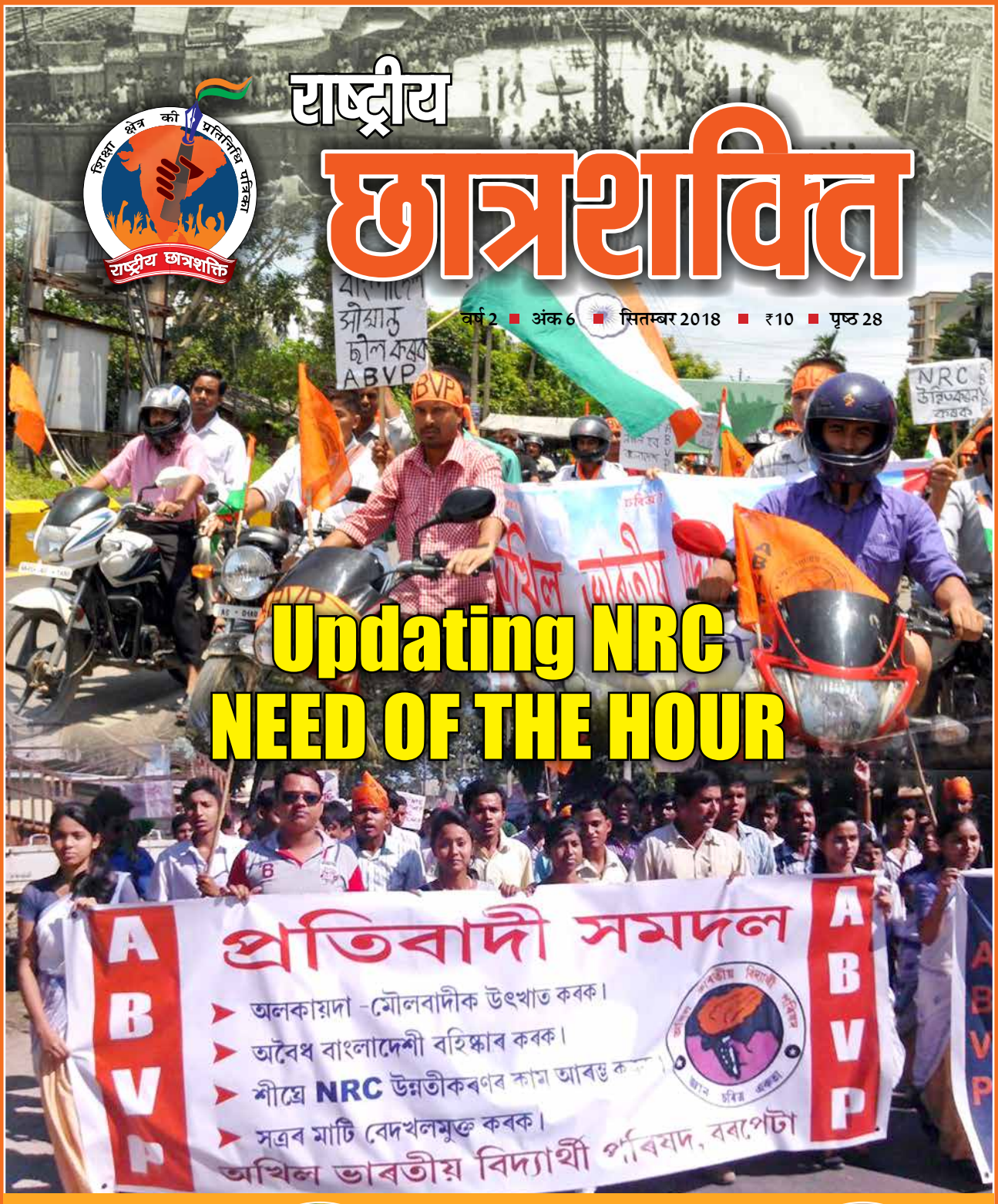

स्मृतिशेष अटल जी

अकादमिक आलस्य के बोझ तले महात्मा गाँधी

स्मृतिशेष

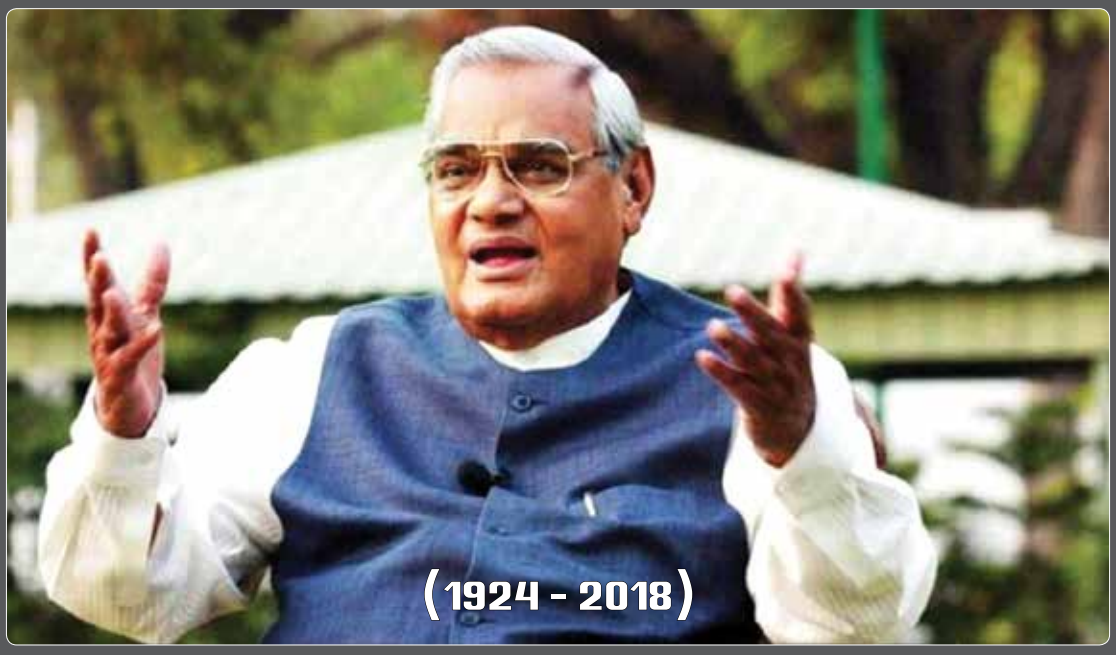

कदम मिलाकर चलना होगा !

बाधाएं आती हैं आएं
घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते-हंसते,
आग लगाकर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

हास्य-रूदन में, तूफानों में,
अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक,
अरमानों को ढलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

कुछ कांटों से सज्जित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन,
परहित अर्पित अपना तन-मन,
जीवन को शत-शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 2, अंक 6
सितम्बर, 2018

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

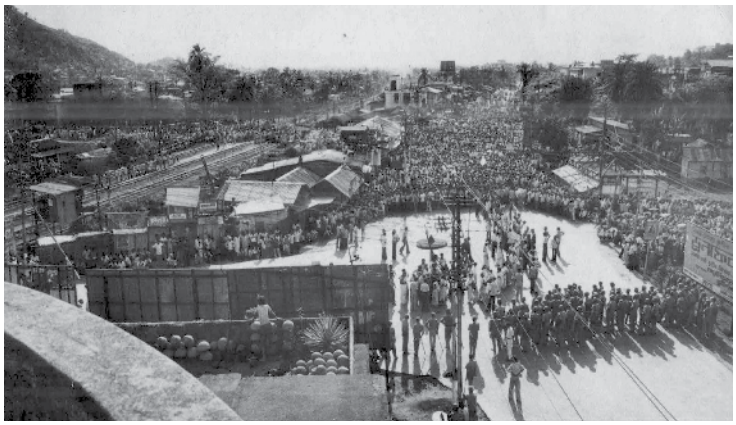

05 **UPDATING NRC : NEED OF THE HOUR**
The purpose of updating of National Register of citizens in Assam is to identify the illegal migrants residing in Assam, who entered Indian territories...

संपादकीय 04
ऐतिहासिक भूमिका पूरी कर रही है अभाविप – अटल जी 09
अटल बिहारी वाजपेयी : संक्षिप्त जीवन परिचय 12
लंबित छात्रवृत्ति – शोधवृत्ति की मांगों को लेकर अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन 13
अकादमिक आलस्य के बोझ तले गांधी 15
अभियांत्रिकी के छात्रों की चिंता हुई खत्म, इंटर्नशिप दिलाने में सहयोग करेगी
साविष्कार लाइव 17
KERALA FLOODS A MAN–MADE DISASTER 18
ABVP MOURNS THE LOSS OF LIVES DUE TO THE FLOODS : DR. S.SUBBIAH 20
शिक्षा में भाषायी आपदा 21
नागालैंड में पहली बार हुआ अभाविप का अभ्यास वर्ग 23
ABVP EXPRESSES DEEP CONCERNS OVER NEFARIOUS ACTIVITIES IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 24
परिचर्चा: देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना कितना सही? 25

वैधानिक सूचना : राष्टीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

श्रद्धेय अटल जी नहीं रहे। अभाविप ने अपनी यात्रा में निरंतर उन्हें अपने निकट पाया। 1948 के उस युवा अटल का सान्निध्य संगठन को मिला जब परिषद ने अपने स्थापनाकाल में ही देश का नाम भारत हो, हिन्दी राष्ट्रभाषा बने और वन्दे मातरम् को राष्ट्रगीत घोषित किया जाय जैसे मौलिक बिन्दुओं को उठाते हुए देश में एक विमर्श खड़ा किया और इसे भारतीयकरण उद्योग का नाम दिया। 24 वर्ष के युवा वाजपेयी इस भारतीयकरण उद्योग के उत्तर प्रदेश के सूत्रधार थे।

यह सहयात्रा निरंतर चलती रही। 1998 में संगठन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उदघाटन के अवसर पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जब उदघाटनकर्ता के रूप में निमंत्रित किया तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और देश के छात्र आन्दोलन में अभाविप के योगदान का उल्लेख किया। कार्यकर्ताओं की वर्तमान पीढ़ी इस आत्मीयता को समझ सके इसलिये स्वर्ण जयन्ती के उदघाटन के अवसर पर श्री वाजपेयी द्वारा दिल्ली के मावलंकर सभागार में दिया गया उनका यह भाषण श्रद्धांजलिस्वरूप इस अंक में समाहित है।

विगत माह राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से भरा रहा है। एक ओर असम में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका के प्रथम प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया वहीं केरल में आई सदी की भीषणतम बाढ़ ने सैकड़ों लोगों का जीवन ले लिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया।

यह स्मरण रखने योग्य है कि 1980 के दशक में आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध चले आंदोलन को राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन के डेढ़ हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी जाकर सत्याग्रह किया। गिरफ्तारी के साथ ही उनमें से अनेक को हिंसा का भी सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, आसाम का विषय समूचे देश का विषय बना और अंततः देश में पहली बार किसी राज्य में विद्यार्थियों की सरकार बनी। दुर्भाग्य से राजनैतिक दांव-पेच में उलझा यह प्रश्न आज भी अपनी परिणति को नहीं पहुंचा है किन्तु चार दशकों से अधिक के कालखण्ड में परिषद ने इसे कभी बिसराया भी नहीं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का प्रकाशन इस दिशा में एक कदम है और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये निर्णायक प्रयास अभी करने बाकी है।

केरल की बाढ़ को महज संयोग या ईश्वरीय प्रकोप कह कर नहीं टाला जा सकता। यह चमचमाते विकास के उन अंधेरे पहलुओं की ओर भी इंगित करता है जहां मनुष्य अपनी लालसा को पूरी करने के लिये प्रकृति के विरुद्ध किसी भी सीमा तक जाता है, दोहन की जगह प्रकृति का शोषण करता है। स्वयं को प्रकृति का एक घटक मानकर अपने कर्तव्यों के पालन से विमुख मनुष्य जब स्वयं को प्रकृति का स्वामी मान लेता है तो इस प्रकार की विभीषिकाएं अवश्यंभावी हो जाती है। लेकिन ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य के कोमल पक्ष को भी उभरने का अवसर मिलता है। केरल की इस त्रासदी में पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। जाति, पंथ, भाषा और विचारधाराओं के बंधन टूट गये और मानवता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस विभीषिका के बीच देखने को मिले। अभाविप के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर लोगों बचाने और उनके लिये सहायता पहुंचाने का कार्य पहले दिन से ही प्रारंभ किया जो आज तक जारी है।

यह पंक्तियां लिखे जाने तक शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी का समाचार आ रहा है और इसके विरुद्ध भारतविरोधी शक्तियों का कोरस शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में संभवतः इस मुद्दे पर बहस और तीखी होगी। छात्रशक्ति अपने पाठकों के लिये इस पर अगले अंक में विशेष सामग्री उपलब्ध करायेगी। प्रस्तुत अंक आपकी प्रतिक्रिया के लिये आपके समक्ष प्रस्तुत है।

शुभकामना सहित,

संपादक

Updating NRC : NEED OF THE HOUR

Shrihari Borikar

Background

The purpose of updating of National Register of citizens in Assam is to identify the illegal migrants residing in Assam, who entered Indian territories after the midnight of 24 March 1971 . Basically, National Register of Citizens (NRC) is a register containing names of Indian citizens. It was first prepared just after 1951 census. In Assam, there was an abnormal increase in the voter list as compared to the 1951 census. It was suspected that large number of illegal migrants, who had crossed over from Bangladesh, found their way into the voter list. This necessitated the exercise of NRC to identify the citizens of India and weed out the illegal Bangladeshi migrants.

The Bangladeshi muslim labourers were brought into assam to cultivate the wastelands. This was encouraged by Sayed Muhammed Sadulla of Muslim league with the intention to create a new vote bank. There were several waves of such infiltration, even after Sadulla, but the largest one was after the 1971 war. In the 1980s, there were demands from ABVP and all other leaders of indigenous communities to update the list of NRC. There were reports that illegal migrations were taking place on a large scale from Bangladesh. The illegal immigration was changing the state's demographic profile and was a big threat to the indigenous cultures and as well as the national security. This was one of the main reasons in the building up of the historic Assam Movement by people of Assam.

The historical background: –

Historically, in the nineteenth and twentieth

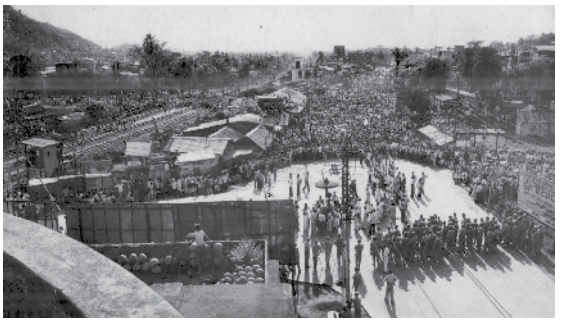

centuries, the colonial Assam saw the influx of Bangla population for the first time. The availability of cultivable wastelands attracted the peasantry from the densely populated neighbouring districts of Bengal like Mymensingh, Bogra, Rangpur and Pabna, Sir Syed Muhammed Sadullah, the first premier of Assam encouraged this flow of Muslim labourers and thus initiated the manipulation of the demographic profile. The Zamindars of Goalpara (a district in Assam) and other landlords encouraged these peasants to settle down in Assam. Leaders of Muslim league, in pre-independence era, viewed this as an opportunity to further their political goals..

The demographic composition of the State from 1901 census reveals that the population in all religious classes had registered growth at varying pace. It was noted that major changes in the demographic profile of districts, such as Goalpara, Nowgong, Darrang and Kamrup, had taken place since 1871 census. Even after independence, this infiltration continued, despite the Liaquat- Nehru pact in 1950.

The release of religion data from Census 2011 stoked fears of a "demographic invasion" in Assam and allowed some political parties to rake up their pet issue of an influx of Bangladeshis ahead of the 2016 assembly polls.

India's Muslim population grew marginally from 13.4% in 2001 to 14.2% in 2011, according to data released by the Central government .On the other hand, Assam recorded the highest decadal increase in the Muslim population, up from 30.9% in 2001 to 34.2% in 2011.The population of Hindus in Assam registered a decrease of 4.4% during this period, going from 64.9% to 61.5%. Though Assam has a sizeable population of indigenous Muslims, the community has invariably been equated with Bangladeshis, whose illegal entry is blamed on poor border management.

The 'foreigner' issue has been a matter of considerable concern after independence. It has been articulated by various sections of the society including student organizations. There is a strong need to place on record, all relevant facts, to arrive at greater clarity on the matter.

Illegal voters–The instant ignition to Assam Movement – assam accord

The death of Shri Hiralal Patwari, sitting Member of Parliament from Lok Sabha representing the Mangaldai LS Constituency on March 28, 1979 necessitated the holding of by-elections, which set in motion the events leading up to the Assam movement. The Assam agitation was born when it was alleged that a large number of names of suspect nationality was included in the voter's list in the Mangaldai LS constituency. ABVP played an important role during this movement. In the 26th National Conference of ABVP Jaipur (1979), there was a thorough discussion on the Assam movement. In the National Executive meeting dated 30 November 1979, a proposal to give full support and co-operation to the Assam movement was passed. On December 6, 1979, a special delegation of ABVP met the then Chief Election Commissioner Mr. SL Shakdhar and demanded the removal of names of foreign nationals from the electoral rolls and postponement of the election until the procedure was completed. On June 8, 1979, the All Assam Students' Union (AASU) sponsored a 12-hour general strike. The demand was-the 'detection, disenfranchisement and deportation' of foreigners. This turned out to be the first of such state-wide protests against infiltration. The Assam Agitation (1979-1985) was a mass movement against illegal immigrants in Assam led by All Assam Students' Union (AASU) and All Assam Gana Sangram Parishad (AAGSP) to compel the Government to identify and expel illegal immigrants. While the agitation programme was largely non-violent, communal incidents were witnessed in some parts of the State particularly in 1983. In 1980 when the Congress party led by Mrs Indira Gandhi came to power at the centre, AASU wrote to Prime Minister Mrs Indira Gandhi on January 18, 1980 drawing her attention to the problem of infiltration. They submitted some broad proposals for the purpose of detecting and deleting the names of foreigners from the electoral rolls based on the NRC of 1951 and thereafter deporting them. The broad proposals for undertaking such an exercise are briefly summarized below: 1) Updating of NRC of 1951, 2) Cross checking of electoral rolls with the updated NRC, 3) Demarcation of the Indo-Bangladesh border and creation of a free uninhabited Belt 4) Issuing of identity cards throughout the Northeast region, 5) Strict maintenance of Birth and Death Register at all Block and Village levels, 6) Raising of additional armed Police battalions and a River Police Force with a view to checking infiltration.

After a 6-year long Assam agitation from 1979 to 1985, a landmark agreement-Assam Accord was signed on August 15, 1985 at the behest of Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. The Assam Accord of 1985 that ended the six-year anti-foreigners' agitation decided upon the midnight of March 24, 1971 as the cut-off date after a long negotiation with the Prime Minister. This agreement between All Assam Students Union (AASU), Government of India & Government of Assam contains some important clauses relating to the foreigner's issue, border fencing, construction of border roads, setting up of border outposts etc.

Role of ABVP in getting the NRC updated

From the time of the Assam Movement of 1979, ABVP has held clear opinion and demands against Bangladeshi infiltration. Since, 1980s ABVP has been raising its' voice in all parts of Assam against the illegal migrants. A huge national level rally was organised named as "Chalo chicken neck" at Kishanganj, from where they warned Bangladeshis to stop illegal migration. On December 6, 1979, a special delegation of ABVP met the then Chief Election Commissioner Mr. SL Shakdhar and demanded the removal of names of foreign nationals from the electoral rolls and postponement of the election until the procedure was completed. ABVP started conducting programs throughout country in support of Assam movement. On July 9, 1980, 40 activists of ABVP organized a 24-hour hunger strike in front of the Parliament House. Later on, national political leaders with leaders from Assam including Janata Party's senior leader Chandrashekhar, BJP's Kalraj Mishra and Lok Dal's George Fernandes met and held a long discussion with ABVP about the ongoing protest against Bangladeshi Infiltration. The group of ABVP activists also met Prime Minister Charan Singh in which Assam's infiltration problem was demanded to be declared as a national threat towards national security, unity and integrity. A meeting was held in JNU in Delhi and consequently another huge public meeting was organized in Bengaluru and Shimoga in Karnataka in order to build awareness about the crisis of Assam and its national importance.

A national conference on this crisis of Assam for the Bangladeshi Infiltration was organized in Delhi on January 4, 1981. Major political parties and social organizations of the country participated in this conference. Senior representatives of 12 organizations including Congress, Lok Dal, CPM, CPI, Janata Party etc. took part in the seminar with AASU, ASTA, AGEA, GUTA from Assam. There was a widespread discussion on the Bangladeshi infiltration problem of Assam in the conference. A permanent committee was formed after this conference in order to take things forward. In Guwahati, AASU leader Bhrigu kumar phukan and Lalit Rajkhowa took part in the meeting organised by this committee. Further A memorandum was given to the Prime Minister by this Committee. At this conference, the solid demand of Detection, Deletion & Deportation for foreign intruders was made for the first time. This conference emphasized that updating of NRC was enlisted in the Assam Accord as a vital point.

The meeting of the National Executive Council held in Mumbai (May 1983), held that the problem of foreign infiltration in Assam was the biggest threat to the national security in future, ABVP decided to organize programs across the country in connection with key leaders associated with the Assam movement. Throughout India, meetings, conferences and press conferences were organized with students' leaders from Assam in order to create sensitivity of the issue nationwide.

ABVP organized 'Shaheed Jyoti Yatra' from Delhi to Guwahati under the leadership of National Secretary Sushil Modi. In September 1983,this yatra, created a nationwide public opinion in support of the Assam movement and supported the activists who were martyred by the repressive congress government, ABVP continued this Yatra nationwide to spread the message of 'struggle saga' of the people of Assam against foreign intrusion by Bangladeshis. The ABVP announced. 'Save Assam Today- Save India Tomorrow' . This announcement was carried out all over the country by ABVP. For the first time any student organization played such a big and ambitious patriotic role at the national level..

Historical Satyagraha of Judges Field (Guwahati) is unforgettable as a nightmare in the history of Assam movement. On October 2, 1983, more than 1000 activists from across the country conducted satyagraha in 'Judges Field' in Guwahati. Thousands of Satyagrahis from

ABVP who came from across the country were forced to return by the police in the same way they came from e.g. buses, railways etc. 800 workers were arrested and sent back to Fakiragram on Assam border. Even after that, more than 1000 workers successfully reached Guwahati. Police ordered lathi charged and launched suppression cycle on Satyagrahis at Judges field where they gathered after arrival. The lathi charge left hundreds of students injured. Former President of ABVP Shri P.V. Krishnabhatta and National General Secretary Dattatreya Hosbale, National Secretary Sushil Modi and Sunil Upadhyay were arrested in this protest.

A Proposal was passed on this topic i.e. 'Disappeared-A National Problem' in the National Convention in Rajkot (1983). The decision was taken to organize national seminar on the infiltration of Assam. National Conference was held in Kolkata on January 12, 1984. For the first time, 144 representatives from 11 provinces of the country participated to discuss on the topic of infiltration. AASU student leader Prafulla Kumar Mahant was invited to give a speech. He recognized the infiltration crisis of the northeast as a 'Killer Disease' for the entire nation.

The Congress-led United Progressive Alliance (UPA) government made amendments in the Indian citizenship law by to appease towards of vote bank. ABVP started a discussion about making alternative laws against this law of protecting intruders and huge effort towards minority appeasement. To stop these efforts by congress, ABVP's leadership declared August 3, 2005, as black day in entire province. About 15000 students / girls tied black and black lace. Earlier, on 17th August, 2005, the ABVP delegation met the Election Commissioner and gave a memorandum demanding removal of illegal voters from the voters list. On 24 August 2005, ABVP's delegation met Union Home Minister Shivraj Patil. In January 2005, huge student rallies were organized in Lakhimpur, Helakandi, Karimganj, Dhubri, Dibrugarh and Guwahati in Assam. In which more than 10000 students took part in these student rallies. Eventually, The Supreme Court cancelled the amendments made in the Citizenship Act. Thus, ABVP was hugely successful in creating a major setback against minority appeasement policy of the Congress government.

Nation Awakening Campaign: From January 23 to February 5, 2006, ABVP launched Nation's 'Jagran campaign' against the Bangladeshi infiltration across the country. Around 50 dignitaries and youth leaders of Assam participated in the programs organized throughout the country which included public meetings, press conferences and intellectual conferences. Many academicians, journalists and student leaders were involved in this campaign. These events were organized at 350 locations in 25 provinces. 25430 students participated in a total of 508 programs in this campaign.

Indo-Bangladesh International Border Survey: During the survey, 129 border villages visited, where 6308 villagers were interacted directly. And in 67 places many issues related to the border with the villagers have been discussed in detail. The situation was discussed after discussing in detail with 20 village chiefs and 69 local Buddhists from these villages. 254 Border Security Force personnel and 25 officials deployed in border security were also interacted. During the survey, it was known in the 27 camps of the Border Security Force. A total of 134 border check posts were examined and there was a direct situation of serious thereat. The team travelled around 78KM of inaccessible area and travelled with bamboo and boats in 45KM.

Chalo Chicken Neck: The border areas of 36KM between Bangladesh and Nepal is very important as it connects the Northeast with India, This area became too sensitive due to the growing influence of Bangladeshi infiltration. Keeping the seriousness of this subject in view, ABVP organized a rally in Kishanganj and Janjagran throughout the country. In this rally, about 50000 students from across the country participated and took concrete decision to act against the Bangladeshi intruders and the demand of Detection, Deletion & Deportation was made again. ■

ऐतिहासिक भूमिका पूरी कर रही है अभाविप - अटल जी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 09 जुलाई, 1998 को नई दिल्ली के मावलंकर सभागार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया उद्बोधन।

श्री वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे।

आदरणीय प्रा. यशपाल जी, राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में आज से सक्रिय हो गये मेरे सहयोगी डा. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी जी, आपटे जी, पाण्डेय जी, गोस्वामी जी देवियो और सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित हो सका। विद्यार्थी परिषद से मेरा नाता उसके जन्म काल से है। किसी छात्र संगठन के लिए 50 साल अबाध गति से प्रगति करते जाना, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते जाना, नई नई योजनाएं हाथ में लेना,चिंतन में और व्यवहार के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास करना अपने में एक बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए विद्यार्थी परिषद का अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे याद है जब उत्तर-पूर्व समस्याओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, अब तो पूरा ध्यान देने का प्रयास हो रहा है उसमें विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने अंतर्राज्यीय सहजीवन का एक प्रयोग प्रारंभ किया। वहां के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे वातावरण में विकसित हो सकें, इस दृष्टि से यह प्रयास प्रशंसनीय था। उत्तर पूर्व के एक मुख्यमंत्री तो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे हैं और उन्हें अभी भी इस बात का गर्व है कि वह विद्यार्थी परिषद से संबंधित थे। विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रवादी

संगठन है, विद्यार्थियों की समस्याओं को टुकड़ों में नहीं उनकी समग्रताओं में देखता है। और इसलिए विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी आते हैं, अभिभावक भी आते हैं, पालक भी आते हैं। विद्यार्थी सबसे कटकर बंटकर समाज में न तो पूरी तरह योगदान दे सकता है और न स्वयं अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकता है। विद्यार्थी नौजवान होते हैं, नागरिक होते हैं, मतदाता होते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन परिषद एक ऐसा संगठन है जो दलीय राजनीति से पृथक रहा है। अनेक दलों के मन में क्या भावना उठती है, उठनी स्वाभाविक है कि यह छात्र संगठन हमारे साथ संबंध क्यों नहीं हो जाता? लेकिन परिषद ने जो निर्णय किया है वह सही निर्णय है। राजनीति भी जीवन का एक हिस्सा है लेकिन जीवन के और हिस्सों की उपेक्षा करके अगर राजनीति सब पर हावी होना चाहती है, खासकर वह राजनीति जो आदर्शों से जुड़ी हुई नहीं है, तो यह राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। विद्यार्थी परिषद ने लोकतंत्र के लड़ाई लड़ी, देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया, विद्यार्थियों ने बलिदान दिए, हिंसा के आघात को सहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद अपने पथ से विचलित नहीं हुई। इसका श्रेय विद्यार्थी परिषद को दिया जाना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन अपेक्षित है। प्राध्यापक यशपाल जी ने जो कुछ कहा वह सब के लिए विचारणीय विषय है। शिक्षा को भी हमने टुकड़ों में बांट दिया जबकि उसे उसकी समग्रता में देखा जाना चाहिए। जो प्रश्न उठते हैं उनका मूलगामी हल खोजने का प्रयास होना चाहिए। प्रो. साहब ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है कारण यह है कि हमने नींव को मजबूत करने की कोशिश नहीं की इतनी बड़ी संख्या मैं लोगों का शिक्षा के अधिकार से और शिक्षा के अवसर से वंचित होना, यह सचमुच में राष्ट्र निर्माण की सही दिशा की ओर संकेत नहीं करता। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात थी, हो नहीं सकी है। प्रयास जारी है। लेकिन उसके साथ और भी शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राएं आगे बढ़ें, इसकी आवश्यकता है।

आज हम नई सदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी-कभी यह लगता है कि यह संक्रमण काल बहुत लंबा हो गया है। लेकिन ऐसा सोचने का कारण नहीं है। जिस देश में गणना मन्वंतरों में होती है वहां 10 साल महत्वपूर्ण होते हुए भी ऐसे कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करते कि उस से निराश होकर हम, हताश होकर वर्तमान के प्रयासों को और भविष्य की योजनाओं को अपनी दृष्टि से ओझल हो जाने दें।

विद्यार्थी परिषद कुछ मूल्यों के साथ प्रतिबद्ध है। परिवर्तन की लहर में कभी-कभी यह आशंका होती है जो कुछ शुभ है, श्रेष्ठ है, सत्य है, शिव है, कहीं वह तिरोहित ना हो जाए। लेकिन इस तरह का डर मन में पालना नहीं चाहिए। इस प्राचीन देश में इसकी संस्कृति ने हजारों वर्ष हर तरह के दौरे देखे हैं। यह देश आगे बढ़ेगा, देश की अस्मिता जागेगी और उसके आधार पर हम शक्तिशाली, सुदृढ़, समृद्धिशाली और स्वावलंबी भारत का निर्माण करने में समर्थ होंगे। इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। संकटों में चुनौतियां होती है। चुनौतियाँ हमारी परीक्षा लेती हैं। हम किस धातु से बने हैं, इसको कसा जाता है। हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं यह भी देखा जाता है और इसलिए संकटों से भागने का सवाल नहीं है। भागकर कहां जाएंगे? अगर हम संकटों से भागेंगे तो संकट हमारे पीछे भागेंगे। जो भी परिस्थिति है उसका सफलतापूर्वक सामना करना होता है। राजनीति के क्षेत्र में मानदंड बिगड़े हैं। वोट की राजनीति ने सारे वातावरण को दूषित कर दिया है। लेकिन उस वातावरण को शुद्ध करना होगा। कुछ समय के बाद लोगों की समझ में, विशेषकर नौजवानों की समझ में यह बात आएगी कि परिवर्तन को अगर स्थाई बनाना है कल्याणकारी बनाना है तो फिर संकीर्ण और क्षुद्र राजनीति का परित्याग करना पड़ेगा।

अंतश्चेतना जाग रही है। इसको और बलशाली बनाने की जरूरत है। छात्र जीवन हमें अवसर देता है। यह चुनौती भी है, अवसर भी है। चुनौती को हम स्वीकार करें, अवसर का लाभ उठाएं। विद्यार्थी परिषद की भूमिका बड़ी रचनात्मक भूमिका रही है। मुझे विश्वास है आने वाले 50 सालों की योजना बनाकर यह विविध कार्यक्रमों को जिनको उन्होंने हाथ में लिया है, उनको सफल बनाएंगे और नए कार्यक्रमों की भी सृष्टि करेंगे। बड़ी मात्रा में मानवीय संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा है। जनबल हमारी पूंजी है। उसको थोड़ा सा सिखाना, थोड़ा सा समझाना और उससे सीखते जाना परिवर्तन की गति को तेज कर सकता है। विद्यार्थी परिषद इस महनीय कार्य में लगी हुई है। मैं विद्यार्थी परिषद को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। उसके नेतृत्व का, उसके कार्यकर्ताओं का, इसमें भाई-बहन सब शामिल

हैं। मैं प्रशंसा उनकी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के रूप में एक ऐसी शक्ति खड़ी हो रही है और खड़ी हो गई है, विद्यार्थी राष्ट्रवादी संगठन है, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध संगठन है, सिद्धांतों पर दृढ़ रहने वाला संगठन है। आरक्षण के सवाल को लेकर काफी उथल-पुथल मची हुई थी तो विद्यार्थी परिषद ने आरक्षण का समर्थन करके बाकी के समाज के सामने एक नई दृष्टि दी थी, बाकी के समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमें समता भी चाहिए, समरसता भी चाहिए। समता कानून दे सकता है, कानून सबको बराबर घोषित कर सकता है, मगर सबको बराबर समझने का चिंतन, सबको बराबर समझकर उनके साथ समान व्यवहार करने का यह दृष्टिकोण कहां से आएगा ? हर बात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता । दरवाजा अगर खटखटाना है एक-एक नागरिक का, एक-एक परिवार का दरवाजा खटखटाना होगा। सचमुच में कपाट को खोलने की आवश्यकता है। और यह कार्य डा. लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा, बिना संवेदना के नहीं हो सकता।

समाज एक जीवमान इकाई है। सुख में, दुख में उसके साथ खड़े रहकर, उसका सहयोग लेकर अगर परिवर्तन किया जाएगा तो वह परिवर्तन स्थाई होगा और वह परिवर्तन कल्याणकारी होगा। एक दृष्टि से विद्यार्थी परिषद एक ऐतिहासिक भूमिका पूरी कर रही है। मैं चाहता हूं और छात्र संगठनों को भी इस तरह का समग्रता का दृष्टिकोण लेकर चलना चाहिए। इस तरह देश की समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ें। प्रतिस्पर्धा तो चलेगी, राजनीति के कारण प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। लेकिन कैसी भी प्रतिस्पर्धा हो, भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा करने का काम अगर नौजवान अपने हाथ उठाते हैं और उसके अनुसार जगह-जगह आशा के, विश्वास के दीपक जलाते जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि जो संकट घिरता हुआ दिखाई देता है उसमें रोशनी की किरण फैले।

यह रोशनी की किरण फैलेगी। इसके लिए नौजवान आगे बढ़ेंगे। निस्वार्थ सेवा, पारदर्शी प्रामाणिकता, राष्ट्र के बारे में चिंतन, इन्हें लेकर विद्यार्थी परिषद सफलता के 50 साल बिताएं हैं। मुझे विश्वास है देश में जो स्थिति पैदा हो रही है वह परिस्थिति हम सबको एक नए ढंग से कर्तव्य पालन करने में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करेगी। सीमा पर खड़ा हुआ जवान अपना दायित्व निभा रहा है। किसान ने अनाज की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे यहां ऐसे उद्योग चल रहे हैं जो विश्व के उद्योगों की टक्कर में टक्कर ले सकते हैं, उससे भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इन सब उपलब्धियों की बात पीछे तक जाती है और देश में हताशा और निराशा का भाव पैदा करने का प्रयास हो रहा है।आज सारे संसार की नजर भारत की ओर लगी है। पोखरण द्वितीय ने सारी दुनिया को हिला दिया है लेकिन दुनिया हिल जाए और हम अपनी जगह पर डटे रहें, जड़ हो जाएँ, गतिमयता छोड़ दें, तेजस्विता का परित्याग कर दें। यह तो उस भावना के साथ मेल नहीं खाता, जिस भावना का हमारे शास्त्रज्ञ ने, टेक्नीशियंस ने, इंजीनियर ने परिचय दिया है। हम चाहते थे क्योंकर अणुशक्ति के मामले में देश पिछड़ा रहे? दुनिया में अनेक देशों में अणु-शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है,शांतिपूर्ण काम के लिए। जहां तक रक्षा का सवाल है उसको अलग किया जा सकता है और अणु - शक्ति विकास के काम में लगे, इस तरह का प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ देशों की जो एकाधिकार वाली प्रवृत्ति है, मोनोपोली वाली प्रवृत्ति है,उस से जूझना पड़ेगा और जूझने में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, आ रही है।

हम पर प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही है,हमने जो कुछ किया सोच समझ कर किया और हम नए प्रतिबंधों की चुनौतियां भी शिकार करने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता इस बात की है सब मिलकर चिंतन करें, सोचें,मिलकर चलें। छोटे-छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर सारे राष्ट्र का सारे विश्व का विचार करें। हम तो ऐसा विश्व चाहते हैं जिसमे एटॉमिक हथियारों की ज़रूरत ही ना हो। क्या ऐसा विश्व बनाने की ओर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? जबानी जमा खर्च ज्यादा हुए हैं, ठोस काम नहीं हुए हैं। मगर चिंतन की इस प्रक्रिया को भी हमने झकझोरा है और हम आशा करते हैं कि विश्व के बड़े राष्ट्र अपने सोचने की दिशा में परिवर्तन करेंगे। जहां तक हमारा सवाल है भारत की नई पीढ़ी मेरे सामने बैठी है,यह नई पीढ़ी सभी संकटों का सामना करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाकर, स्वालंबन की भावना को बढ़ाकर हम न केवल वर्तमान चुनौती का सामना कर सकते हैं, अपितु आने वाले सवालों का भी हल ढूंढ सकते हैं। मुझे आपने आमंत्रित किया, उद्घाटन करने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। ■

अटल बिहारी वाजपेयी : संक्षिप्त जीवन परिचय

भारतीय राजनीति के देदीप्यमान सूर्य भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के एक ऐसे सपूत थे, जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात भी अपना जीवन देश और देशवासियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु समर्पित किया।मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर, 1924 को अटल जी का जन्म हुआ। पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी को तब शायद ही अनुमान रहा होगा कि आगे चलकर उनका यह नन्हा बालक सारे देश और सारी दुनिया में नाम रौशन करेगा और भारत माँ के अमर सपूतों में अग्रिम पंक्तियों में अपना नाम दर्ज करवाएगा।

अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज तथा कानपुर के डी. ए. वी. कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की और राजनीति विज्ञान में एम. ए.की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की।

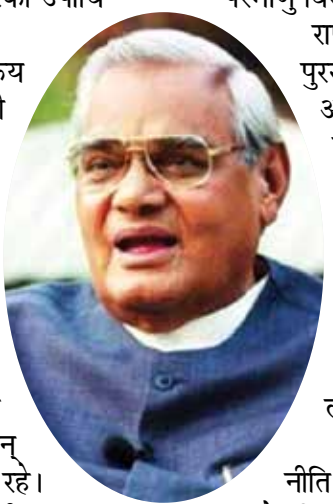

भारतीय स्वातंत्र्य-आंदोलन में सक्रिय योगदान कर 1942 में मात्र 17 वर्ष की आयु में जेल गए। वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य और सन् 1951 में गठित राजनैतिक दल 'भारतीय जनसंघ' के संस्थापक सदस्य थे। सन् 1966-67 में सरकारी प्रत्याभूतियों की समिति के अध्यक्ष, सन् 1967 से 70 तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तथा सन् 1968 से 73 तक वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। सन् 1975-77 के दौरान आपातकाल में बंदी रहे। 1977 से 79 तक भारत के विदेश मंत्री, सन् 1977 से 80 तक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, सन् 1980-86 भाजपा अध्यक्ष, सन् 1980-84, 1986 तथा 1993-96 के दौरान भाजपा संसदीय दल के नेता रहे। सन् 1957 में दूसरी लोकसभा के लिए प्रथम बार निर्वाचित हुए।. सन् 1962-67 और 1986-91 के दौरान राज्यसभा के सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। और सन् 1988 से 89 तक सार्वजनिक प्रयोजन समिति, सन् 1988-90 में संसद् की सदन समिति तथा व्यापारिक परामर्श समिति के सदस्य रहे। सन् 1993 से 1996 तक तथा 1997 -98 में विदेश नीति समिति के अध्यक्ष बनाये गए। अटल जी सन् 1993-96 और 1996-97 में लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। सन् 1999 में लोक सभा में भाजपा संसदीय दल के नेता और सन् 2004 में भाजपा और एनडीए संसदीय दल के अध्यक्ष रहे।

भारत के बहुदलीय लोकतंत्र में अटल जी ऐसे एकमात्र राजनेता थे, जो प्रायः सभी दलों में स्वीकार्य रहे। 16 मई, 1996 से 31 मई, 1996 तथा 1998 - 99 और 13 अक्तूबर, 1990 से मई, 2004 तक तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में जहां इन्होंने पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने हेतु अभूतपूर्व कदम उठाए वहीं अंतर - राष्ट्रीय दवाबों के बावजूद गहरी कूटनीति तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए पोखरण में परमाणु विस्फोट किए तथा करगिल-युद्ध जीता।

राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण पुरस्कार, सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किये गए। अटल जी ने भारत की संस्कृति, सभ्यता, राजधर्म, राजनीति और विदेश नीति की गहरी समझ के साथ बदलते राजनैतिक पटल पर गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक बनाने, चलाने और भारत को विश्व के शक्तिशाली देशों की अग्रिम पंक्तियों में लाकर खड़ा किया।

राजनीति में दिग्गज राजनेता, विदेश नीति में संसार भर में समादृत कूटनीतिज्ञ, लोकप्रिय जननायक और कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ ये एक अत्यंत सक्षम और संवेदनशील कवि, लेखक और पत्रकार भी रहे। राष्ट्र धर्म (मासिक), पाञ्चजन्य (साप्ताहिक), स्वदेश (दैनिक), और वीर अर्जुन (दैनिक) जैसे पत्र-पत्रिकाओं का संपादन और अनेक विषयों पर अटल जी ने पुस्तकें लिखी। लेखक होने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी उच्च कोटि के कवि भी थे। देश की आर्थिक उन्नति, वंचितों के उत्थान और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण की भावना के साथ अपना सर्वस्व जीवनपर्यंत देश के लिए समर्पित किया। अटल जी 16 अगस्त २०१८ चिर निद्रा में लीन में हो गये। ■

लंबित छात्रवृत्ति - शोधवृत्ति की मांगों को लेकर अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

छात्रवृत्ति - शोधवृत्ति एवं छात्रावासों की विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। अभाविप के द्वारा बीते 30 अगस्त को देश के सभी राज्यों की राजधानी तथा जिला मुख्यालयों पर धरना एवं प्रदर्शन कर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निश्चित समय सीमा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति व शोधवृत्ति समय से न दिये जाने पर प्रश्न खड़ा किया, साथ ही सभी प्रकार की रुकी हुई छात्रवृत्तिओं के वितरण की मांग की।

देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान मुंबई में रैली को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि आज प्रत्येक छात्र को मिल रही छात्रवृत्ति अपर्याप्त है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अभाविप यह मांग करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्री- मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रति वर्ष राशि न्यूनतम 12000 रूपये तक बढ़ाई जाये तथा शेष वर्ग के लिए भी उसी अनुसार राशि बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष छात्रवृत्तियों में 2003 से कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इन छात्रवृत्तियों को तत्काल पांच गुना बढ़ाना चाहिए, जिससे सम्मानजनक तथा सराहनीय राशि से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मध्य शिक्षा का प्रसार हो सके।

अव्यवस्था का तुरंत समाधान करे सरकार : जी. लक्ष्मण

अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री जी लक्ष्मण ने हैदराबाद में आयोजित छात्र अधिकार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति एवं शोधवृत्ति की राशि को सरकार अविलंब निर्गत करे साथ ही वितरण में हो रही अव्यवस्था का सुधार कर पारदर्शिता लायें। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सड़क पर आने को विवश होंगे।

मूल्य सूचकांक से जुड़े छात्रवृत्ति : श्रीनिवास

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में निकाली गई छात्र अधिकार रैली को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि अभाविप वर्षों से लगातार छात्र हित तथा राष्ट्र हित में कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। एससी, एसटी तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को समय से छात्रवृत्ति एवं शोधवृत्ति प्राप्त हो तथा छात्रवृत्ति को मूल्य सूचकांक के साथ

क्या है अभाविप की मांगें –

1. राजीव गांधी शोधवृति, राष्ट्रीय शोधार्थी शोधवृत्ति, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति लंबे समय से प्रलंबित है। सभी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं शोधवृत्ति तत्काल 15 दिन के अंदर जारी करते हुए राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. 2003 में एक बार प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई थी, तत्पश्चात गत 15 सालों में किसी भी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान समय में छात्रवृत्ति न्यूनतम 2250 व अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष की दर से छात्रों को मिलती है। अतः महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा न्यूनतम छात्रवृत्ति 12,000 प्रतिवर्ष की जाये व उसी मात्रा में वर्गवार अधिकतम छात्रवृत्ति निश्चित करें।
3. छात्रवृत्ति को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाए जिससे छात्रवृत्ति महंगाई के साथ समयानुसार परिवर्तित होगी।
4. अनुसूचित जाति के छात्रों में शोध शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ रहा है, परंतु राजीव गांधी शोधवृत्ति के अंतर्गत केवल 2000 छात्रों को शोधवृत्ति दी जाती है। अतः अनुसूचित जाति के छात्रों में शोध वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए शोध की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए।
5. वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु राष्ट्रीय ओबीसी शोधवृत्ति 300 छात्रों को दी जा रही है, जो कि अपर्याप्त है। अतः छात्र संख्या के अनुपात में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए।
6. वर्तमान में शोधवृत्ति एवं छात्रवृत्ति की राशि अत्यंत विलंब से आ रही है। शोधवृत्ति एवं छात्रवृत्ति प्रत्येक माह समय पर मिले ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे पढ़ाई में सुविधा हो।
7. छात्र संख्या के अनुपात में छात्रावासों की सुविधा पर्याप्त नहीं है। अतः पूरे देश में छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाए।
8. छात्रावास में छात्रों के विकास हेतु लाइब्रेरी, खेल, साहित्य, कैरियर, मार्गदर्शन व व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
9. छात्रावास में अधीक्षक, रसोईया, सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मचारी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छात्रावास कुशल संचालन में सुनिश्चित हो सके।
10. स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रत्येक जिला केन्द्र पर की जाए।
11. स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जिला स्तर पर विशेष छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
12. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में छात्राओं का शिक्षा में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कन्या छात्रावासों की संख्या में वृद्धि कर विकास खंड स्तर पर सुरक्षित कन्या छात्रावास उपलब्ध कराये जाये।

जोड़ा जाए। छात्र संख्या के अनुपात में छात्रावास बनाए जाएं आदि मांगों को लेकर आज देशभर में विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रव्यापी धरना दिया है और विद्यार्थी परिषद इस विषय को समाधान तक ले जाने हेतु संकल्पित है। वहीं दिल्ली प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि इस छात्र अधिकार रैली के माध्यम से हम अपनी मांगों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि छात्र हित में हमारी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

मांगे न पूरी न हुई तो होगा उग्र आंदोलन : श्रीहरि बोरिकर

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति एवं शोधवृत्ति पिछले कई सालों से लंबित है। सरकार को छात्रवृत्ति की समस्या का समाधान करते हुए सभी मंत्रालयों को आपस में समन्वय करते हुए शोधवृत्ति तथा छात्रवृत्ति को एक मंच पर वितरण करने की संभावना तलाशनी चाहिए। सरकार जल्द से जल्द छात्रों की मांगों को पूरा करे वरना सरकार को छात्रों के उग्र आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। ये बातें अभाविप के अखिल भारतीय राज्य विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख श्रीहरि बोरिकर ने कहीं। वे अहमदाबाद में आयोजित छात्र अधिकार रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किये जाने की बात कहीं। ■

महात्मा गांधी की सार्धशती पर विशेष आलेख श्रृंखला - 1

अकादमिक आलस्य के बोझ तले महात्मा गांधी

| जयप्रकाश |

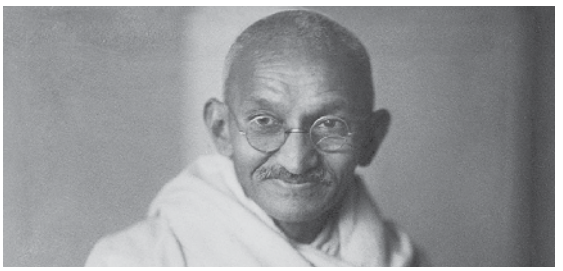

भारत में पसरे अकादमिक आलस्य का असर गांधी के आकलन पर भी साफ देखा जा सकता है। इस आलस्य के कारण ही गांधी या तो 'प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद' बन जाते हैं अथवा 'हास्यास्पद गलतियों का घृणास्पद पुतला' बन जाते हैं। आकलन का यह तरीका खुद को अंतिम सच घोषित कर चुके पैगम्बरों का तो हो सकता है, किसी व्यक्ति को उसकी खूबियों-खामियों, क्षमताओं-अक्षमताओं के अनुपात में स्वीकार या अस्वीकार करने वाले संतुलित दृष्टिकोण का नहीं। एक राष्ट्र या व्यवस्था यदि पैगम्बरी दृष्टिकोण को अपनाती है तो उसमें सृजनात्मकता का तो लोप होता ही है, आकलन की त्रुटियां उसे सही निर्णय लेने में भी बाधा पहुंचाने लगती है और एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है।

गांधी को लेकर समाज में एक ऐसी ही विभ्रम की स्थिति दिखाई पडती है। उनकी सीमाएं और सामर्थ्य दोनों इतने प्रत्यक्ष हैं कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी कारण कई बार आम व्यक्ति उनका आकलन अधिक सटीक ढंग से कर पाता है। पर अकादमिक जगत? अकादमिक जगत की त्रासदी यही रही है कि या तो उनकी सीमाओं को दार्शनिक लबादा पहनाकर सामर्थ्य बताने की कोशिश करता है या अहिंसा को निष्क्रियता का समानार्थी घोषित कर उनके खूबियों को भी खामी के तौर पर पेश करता है।

आखिर इसे क्यों स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनकी हिंदू-मुस्लिम एकता की अवधारणा में तुष्टीकरण के तत्व दिखलाई पड़ते हैं। हमें उनका मूल्यांकन करते समय यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने हिंदुत्व के उदार नजरिए से इस्लाम को देखा और उसका मूल्यांकन किया। यदि उन्होंने इस्लाम के नजरिए से हिंदुत्व को देखने का कष्ट उठाया होता तो वह हिंदू-मुस्लिम एकता पर अधिक संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर पाते। जब एक पंथ का सबसे बड़ा आग्रह यह है कि उसका पैगंबर ही अंतिम और एकमात्र सच है तो ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम के समन्वयकारी दृष्टिकोण के लिए स्पेस ही कितना बचता है? क्योंकि यहां तो संवाद करने, खुद को बदलने को दीन से खारिज होने जैसा है। गांधी इस मूलभूत सच को पकड़ने से चूके और एक ही पक्ष से देने-बदलने की अपील करते रहे। इससे संवाद, शांति और समन्वय का एक भ्रम तो पैदा हुआ लेकिन देश में ये चीजें स्थापित न हो सकीं।

इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि गोसरंक्षण-गोसंवर्द्धन, मतांतरण, राष्ट्र और भाषा पर उनका दृष्टिकोण नितांत हिंदुत्ववादी है। मतांतरण को लेकर उनका रुख इतना स्पष्ट और कड़ा था कि आज का राजनीतिक विमर्श उन्हें आसानी से साम्प्रदायिक और कट्टरपंथी ठहरा सकता है। जब पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीयता की लहर चल रही थी तब उन्होंने राष्ट्रवाद की पैरोकारी करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता की पूर्व शर्त है। गोसंरक्षण और गोसंवर्द्धन से उनके लगाव के कारण उन्हें पिछड़ा और अप्रगतिशील ठहराया जाता रहा। औद्योगीकरण और शहरीकरण के चलन के बीच गांवों को राजनीति-अर्थनीति का केंद्र बताना उनको एक अलग श्रेणी में पहुंचा देता है।

दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद गांधी को समग्रता में देखने के बजाय, अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार-अस्वीकार करने का चलन पैदा हुआ। अकादमिक जगत इस चलन से कुछ अधिक ही प्रभावित हुआ। संभवतः इस खंडित दृष्टि के कारण ही भारतीय सार्वजनिक विमर्श में गांधी की उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है, हर पक्ष उनके विचार और व्यक्तित्व पर चर्चा करता है, लेकिन कोई भी पक्ष उन्हें पूरी तरह अपना नहीं मानता, उन्हें विरोधी खेमे में रखता है। कट्टर मुसलमानों के लिए वह चतुर हिंदू नेता थे, तो कुछ हिंदू उन्हें मुसलमानों का पक्षधर मानते रहे हैं। हरिजनों के लिए वह सवर्णवादी थे, तो सवर्णों के लिए हरिजनवादी। साम्यवादियों के लिए वह

'पूंजीवादी एजेंट' थे और पूंजीवादी उन्हें मशीनों का विरोध कर समानता का स्वप्न देखने वाला साम्यवादी मानते थे। संतों के लिए वह एक व्यावहारिक नेता थे और राजनेताओं के लिए अव्यावहारिक संत। आधुनिकतावादी उन्हें पिछड़ेपन का प्रतीक मानते हैं और पुरातनपंथियों के लिए वह धर्म भ्रष्ट करने वाले परिवर्तनों के वाहक रहे हैं। अकादमिकों के लिए वह कम पढ़े-लिखे व्यक्ति और सामान्य व्यक्तियों के लिए उच्च कोटि के दार्शनिक और साधक। आखिर एक ही व्यक्ति के प्रति इतने विरोधाभासी निष्कर्ष कैसे निकल सकते हैं? यह एक जटिल प्रश्न है और गांधी के संदर्भ में निकाले जाने वाले निष्कर्षों की एकांगिकता की तरफ संकेत भी। उन्हें जिन प्रचलित दृष्टिकोणों या उपलब्ध उपकरणों के जरिए समझने की कोशिश की जाती रही है, वे बौने साबित हुए हैं। अभी तक गांधी को उनके मौलिक-लोकधर्मी और प्रयोगधर्मी परिप्रेक्ष्य में देखने-समझने के बजाय प्रक्षेपण पद्धति से देखने समझने की कोशिश अधिक हुई है।

यदि किसी विचार या व्यक्ति को प्रक्षेपण पद्धति से समझने की कोशिश की जाती है, तो गलत निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अध्येता अपने पूर्वाग्रहों का संबंधित व्यक्ति या विचार पर प्रक्षेपण करता है और वही निष्कर्ष निकाल लेता है, जो वह निकालना चाहता है। गांधी जैसे व्यक्ति के संदर्भ में तो गलत निष्कर्ष की संभावना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके चिंतन का कैनवास बहुत बड़ा है और मौलिक भी। उनकी विशालता सभी चिंतन धाराओं को स्पर्श करती है, लेकिन उनकी सत्य के साथ प्रयोग करने की आदत, सभी पक्षों द्वारा उन्हें गलत समझे जाने की संभावना को बढ़ा देती है।

गांधी स्वयं में एक अलग 'टाईप' हैं और उस 'टाईप' के आधारभूत तथ्यों को समझे बिना उनकी सीमाओं और संभावनाओं का सम्यक आकलन नहीं किया जा सकता। गांधी अधेड़ उम्र में जब भारत वापस आते हैं, तो गोखले की सलाह पर लगभग पांच वर्ष भारतीय लोक को समझने में लगाते हैं। इस अवधि में लोक के जरिए सत्य से साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे थे और समाज के बारे में अपनी अवधारणाओं को गढ़ रहे थे। बाद में भी वह लोक से गहरे तक जुड़े रहे यानी उनकी अवधारणाओं का स्रोत किताब और शास्त्र से कहीं अधिक लोक था। लोक पर इस निर्भरता के कारण ही उनकी संकल्पनाओं में ऐसी कमजोरी के दर्शन होते हैं, जो लंबे समय से आक्रांत समाज में हो सकते हैं। भारतीय समाज की विशिष्ट संरचना तथा सनातन आधारों पर आधिष्ठित संस्कृति के कारण लंबी पराधीनता के बाद भी तत्कालीन समाज में कुछ परंपराएं इतनी स्वस्थ रूप में प्रवाहमान थी कि उनके शुद्ध तत्त्व से परिचित हुआ जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ परंपराएं सड़ांधता का शिकार हो चुकी थीं कि उन्हें आसानी से त्यागा जा सकता था। इन दोनों छोरों के बीच बहुत कुछ ऐसा था, जिनकी उपयोगिता-अनुपयोगिता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। इनके बारे में टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त शोध की आवश्यकता थी। गांधी ने स्वस्थ को स्वीकारा, अस्वस्थ को नकारा एवं कुछ का शोधन किया।

उदाहरणतः राजनीति और धर्म के अंतर्संबंधों के बारे में उनकी संकल्पना को लिया जा सकता है। वह मानते थे कि राजनीति एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्य है। राजनीति और धर्म के पृथक्करण से अंततः राजनीति स्वार्थी हो जाती है और धर्म पंगु बन जाता है। परंतु राजनीति की संपूर्ण जटिलताएं स्वीकार करते हुए भी धार्मिक बना रहा जा सकता है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी राजनीति 'साम' तक सीमित रखी। 'दाम', 'दंड', 'भेद' के बारे में उनके मन में हिचक बनी रही। इसी हिचक के कारण 'गीता' तो आजीवन उनकी मार्गदर्शक बनी रही, लेकिन जिस महाभारत का यह हिस्सा है, उसे उन्होंने मानसिक-मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिया। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सके कि कृष्ण जैसा तत्त्वदर्शी, धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 'युद्धाय कृतनिश्चय' के लिए प्रेरित कर सकता है।

यदि इसी ग्रंथ के शांतिपर्व में उल्लिखित 'राजधर्म' की महत्ता और जटिलता से उनका पूर्ण परिचय हुआ होता, तो संभवतः यह हिचक टूटती। ऐसा न हो पाने के दो कारण रहे होंगे। पहला गांधी की लोकधर्मिता और दूसरा भारतीय संकल्पनाओं के विस्तृत शोध प्रबंधों का अभाव। गांधी लोक जीवनदर्शन और जीवन शैली से तत्त्व खींचकर संकल्पनाएं गढ़ते थे। उस समय लोकजीवन में राजधर्म के प्रति उदात्त भाव तो बचा हुआ था, लेकिन हिंसा के प्रति घृणा के स्तर तक भावना विद्यमान था। इस कारण उनकी राजनीतिक अवधारणा शिखर तक नहीं पहुंच सकी। दूसरे, लोकधर्मी होने के बावजूद गांधी अध्ययन भी खूब करते थे। 1924 की उनकी जेल डायरी उनकी अध्ययन क्षमता का प्रमाण है। अध्ययन की इस प्रवृत्ति के बावजूद यदि वह राजनीति की भारतीय संकल्पना को सम्यक ढंग से नहीं समझ सके तो उसका कारण भारत केन्द्रित अध्ययन का शैशवावस्था में होना था। यदि उन्हें भारतीय संकल्पनाओं पर विस्तृत सामग्री उपलब्ध हो पाती, तो शायद उनकी वैचारिक यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो पाती। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी इन सीमाओं के बावजूद गांधी ने भारतीय संकल्पनाओं को सामाजिक रूप देने और

उन्हें सार्वजनिक विमर्श में प्रतिष्ठित करने का भागीरथ प्रयास किया था।

लोकधर्मिता के साथ प्रयोगधर्मिता भी विशिष्ट गुण था। बने-बनाए सत्यों के बजाय वह स्वनिर्मित अनुभूत सत्यों पर विश्वास करते थे और 'सत्य के साथ प्रयोग' करते रहे। एक स्पष्ट सभ्यतागत समझ के बावजूद वह व्यावहारिक धरातल पर निरंतर प्रयोगधर्मी रहे। इसीलिए एक तरफ वह 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर केवल एक शब्द बदलने के लिए तैयार हुए थे। दूसरी तरफ एक चौरी - चौरा कांड के कारण जिस गांधी ने पूरे असहयोग आंदोलन को ठप्प कर दिया था, वही गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई राष्ट्रव्यापी हिंसा के खिलाफ मौन रहे। इसी तरह जीवन के सांध्य काल में ब्रह्मचर्य को लेकर उनके प्रयोग भी उनकी स्वीकार्यता और छवि दोनों को प्रभावित कर रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रयोगधर्मिता के लिए आवश्यक साहस को बनाए रखा।

एक ऐसे दौर में जब अकादमिक आलस्य और पैंतरेबाजी ने गांधी को अहिंसा और पंथनिरपेक्षता के नारों तक सीमित कर दिया है, यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें सम्पूर्णता में समझा जाए। उनकी सीमा और सामर्थ्य, दोनों को खुलेमन से स्वीकार किया जाए। यह स्वीकृति-अस्वीकृति आज के भारत की कई गांठें खोल सकती है, उसकी भविष्य की यात्रा को अधिक सृजनात्मक और साहसपूर्ण बना सकती है। यह श्रृंखला गांधी को खुलेमन से समझने का प्रयास है ताकि उनकी जीवतंता को अपनाया जा सके और प्रेतछाया से मुक्ति मिल सके। ■

अभियांत्रिकी के छात्रों की चिंता हुई खत्म, इंटर्नशिप दिलाने में सहयोग करेगी साविष्कार लाइव

अखिल भारतीय तकनीकी अनुसंधान परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) में स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों के लिए किसी उद्योग अथवा शोध संस्थान से इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिये जाने के बाद औसत छात्रों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। क्योंकि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आसानी से विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिल जाता है लेकिन औसत छात्रों को ऐसे मौके नहीं मिल पाते थे। इन छात्रों को अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि साविष्कार लाईव, ऐसे छात्रों को इंटर्नशिप दिलवाने मदद करेगी। इस बाबत साविष्कार लाईव के द्वारा भोपाल में 29 अगस्त को इंटर्नशिप की नीतियों पर सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया गया ।

परिचर्चा में इंटर्नशिप के बारे जानकारी देते हुए एआईसीटीई के उप-निदेशक नीतू भगत ने कहा कि इंटर्नशिप अनिवार्य होने से छात्रों को अब कक्षा के बाहर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा और इस प्रशिक्षण पर उन्हें क्रेडिट प्वाइंट भी दिए जायेंगे, स्नातक पूरा करने के लिए छात्रों के पास कम से कम इंटर्नशिप प्रोजेक्टस के 14 से 20 अंक जरूरी होंगे, जबकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए 10 से 16 अंक लाना अनिवार्य है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन ने कहा साविष्कार लाईव और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित यह परिचर्चा छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नीतियों को बनाते समय कई बार नीति नियंताओं को भी उक्त नीति के दूरगामी प्रभाव व समस्याओं का अंदाजा नहीं होता है, वैसे समय छात्रों की समस्याओं के निदान शिक्षकों के हाथों में होती है। अभाविप के प्रकल्प के रूप में कार्य कर रहे साविष्कार लाईव द्वारा विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र के छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु एक मंच दिया जाता है, जहां से वे लाभान्वित होकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं।

साविष्कार लाईव पोर्टल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन शुक्ला के मुताबिक कार्यशाला से प्राप्त होने वाले विचारों को संकलित कर उन्हें संबंधित शासकीय निकायों तथा उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि साविष्कार के माध्यम से प्रदत्त इंटर्नशिप की मदद से छात्र स्वयं को उद्योगों एवं नियोक्ताओं की आवश्यकतानुसार अपने कौशल एवं ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साविष्कार लाईव पोर्टल के द्वारा छात्रों को इंटर्नशिप से संबधित सभी बिंदुओं पर उचित मार्गदर्शन व सहयोग उपलब्ध है। परिचर्चा में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, प्रसिद्ध उद्योगपति, शिक्षाविद, शासकीय अधिकारी समेत सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। ■

Kerala floods a man-made disaster

| G Sreedathan |

The Kerala State Electricity Board and state irrigation department, which maid the dams in Kerala, have opened the shutters of many dams without any preparation or warning resulting in massive death and destruction in the state. According to a Malayalam media report, even the district collector was not informed about the move.

Gushing waters of Banasur dam, which was opened without prior warning, had ravaged the entire Wayanad district. Flood-prone areas such as Panamaram, Venniyodu. Kottathara, Kurumony and Vellamunda areas were completely submerged. A majority of the houses in these areas were inundated and many lives were lost.

According to the report, three out of the four shutters of Banasur dam were first opened on July 15. At that time, advance warning was given. But later, before further raising the shutter level up to 290 cm and opening the fourth shutter, no prior warning was given. The district collector and village officer were not informed before raising the height of shutters.

Even before sounding Red Alert, three dams in the Sabari Giri project were opened in the middle of the night which flooded banks of the Pampa river. By the time Red Alert was sounded on August 15, the entire Pampa basin was under water. Experts say if alert was sounded in advance, the damage could have been much less.

"I never expected that the water from the dam would flood the houses so fast. Even though the government had issued a red alert, we never thought that all the four shutters of the dam would be opened at the same time. If they had been opened one by one, we could have moved our belongings to safe places," MC Joseph, a resident of Kuttikkatt village, told First Post.

The authorities flouted the guidelines of National Disaster Management on opening of dams. All dams, except Mullaperiyar and Idukki dams, should opened only after informing the district collector who is also the head of district disaster management department.

Senior BJP leader K Surendran has said Electricity minister MM Mani and electricity

board chief engineer should be tried on murder charges. Their negligence and ineptitude led to the biggest tragedy that struck Kerala so far. Congress leader Satheesan also echoed similar demand.

The exact number of human casualty is yet to be confirmed. However, initial estimate indicate that more than 400 people have lost their lives in the avoidable tragedy.

The state government also failed to hand over the responsibility of relief operation to the army, National Disaster Response Force and other central agencies. Initially, the government was also not ready to call in the army. The entire state machinery had collapsed and the army contingent had to wait for hours to get the permission of District Collectors and Tahsildars for carrying out rescue operation. Ironically, an NDRF team had to wait for 12 hours to get orders from a Tahsildar to begin the rescue operation.

The rivers -- Achankovil, Pampa, Periyar -- were in spate and deluding vast stretches of land turning it into a watery grave. People were thrown into the whirlpool of uncertainty and fear. Perched on the rooftops of their houses they saw hungry waters rising to swallow them. There was no one to look up. At that time came Sewa Bharati and RSS workers in thousands, throwing their own lives at risk to save lakhs of people trapped in houses filled with water.

Matchless efforts

The rivers -- Achankovil, Pampa, Periyar -- were in spate and deluding vast stretches of land turning it into a watery grave. People were thrown into the whirlpool of uncertainty and fear. Perched on the rooftops of their houses they saw hungry waters rising to swallow them. There was no one to look up. At that time came Sewa Bharati, ABVP and RSS workers in thousands, throwing their own lives at risk to save lakhs of people trapped in houses filled with water. Even before the world came to know about the gravity of the flood, local activists of Sewa Bharati, ABVP and RSS volunteered to help people who were vulnerable. Thousands of swayamsevaks swung into action in the worst-affected areas of Chengannur, Paravur, Aluva and Alappuzha, along with fisher folk, army and NDRF men.

Although they were not trained to undertake operations at dangerous situations like these, their understanding of the local topography helped Army and disaster management officials carry out effective rescue operations. While rescuing stranded people from flooded-hit areas, they did not look at the caste or religion of the victims. Swayamsevaks from the fishermen community came with their boats and rescued thousands. Their experience, expertise and courage gave a big boost to the rescue operation.

From the beginning of the tragedy, Sewa Bharati was able to provide food and clothes to the victims in relief camps. The wide network of the Sangh-inspired organisations helped Sewa Bharati to collect and supply relief materials in a short span of time. All these efforts went on like a well-oiled machine.

Sewa Bharati volunteers undertook rescue operations in Paravoor Aluva, Kadangallur, Varappuzha and Kalady, which were inundated due to flooding in the Periyar river. Fishermen from Marad, Payyoli and Kozhikode led the rescue operations in Eranakulam. Sewa Bharati deployed about 300 boats in the operation.

Sewa Bharati's presence was abundantly seen in areas like Kottayam, Pala, etc. A major rescue work was undertaken in worst affected Ranni and Venmony where gushing waters of the Pampa river had wreaked havoc. Sewa Bharati runs about 300 camps directly and sends food and other relief materials to a few others. ■

ABVP mourns the loss of lives due to the floods : Dr. S.Subbiah

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) Kerala Unit immediately started their rescue, relief and rehabilitation activities in various parts of the state as soon as the state faces an unprecedented deluge. From the beginning of the tragedy, ABVP was able to provide food and clothes to the victims in relief camps. The wide network of Vidyarthi Parishad inspired other organisations to help ABVP to collect and supply relief materials in a short span of time.

ABVP has setted up about 150 camps directly in major flood affected areas and supplying food and other relief materials to the needy ones and many relief camps had also been set up in other districts. Parishad's presence was abundantly seen in areas like Kottayam, Pala, etc. A major rescue work was undertaken in worst affected Ranni and Venmony where gushing waters of the Pampa river had wreaked havoc.

More than 25000 volunteers of ABVP are directly engaged in the rescue and relief activities since last three weeks. Many of them are the ones who have lost their own houses to floods. Karyakarta are paying special attention to helping residents of the worse affected districts. Around 20,000 victims who were cut off from the rest of the world were rescued by the volunteers of ABVP. Apart from life saving kit, they are distributing other goods such as vessels, clothes, groceries, medicines and other essentials to the victims and to the relief camps.

While sending condolences to the families of victims, national president Dr. S. Subbiah said, "ABVP mourns the loss of lives due to the floods. While ABVP members are continue to work for the flood victims, I appeal to people of India to contribute to Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad and help us to serve the flood victims better."

The national general secretary of ABVP Shri. Ashish Chauhan said, "ABVP stands in solidarity with the families who lost their beloved ones to the floods. To help the flood victims, all units of ABVP across India will start fund collection. ABVP will leave no stone unturned to help those affected by the floods." The Parishad has called upon all countrymen and islanders in particular to come forward for the noble cause and contribute to Akhil Bharathiya Vidyarthi Parishad Kerala State Branch, State Bank of India Trivandrum City Branch, Account No.: 37084506038, IFSC: SBIN0070028, Vidhyarthi Seva Trust, State Bank of India) ■

शिक्षा में भाषायी आपदा

| चन्दन आनन्द |

स्वतंत्रता उपरांत भारतीय राजनीति में भारतीय विचार को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करने वाले पं. दीनदयाल उपाध्याय एक बात अक्सर कहते थे, "अगर प्रश्न भारत के हैं तो उत्तर भी भारत से ढूंढने होंगे। हम भारत के प्रश्नों को विदेशी उत्तरों या उनका अनुसरण करके हल नहीं कर सकते"। श्री दीनदयाल उपाध्याय का यह विचार भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में भी था। 25 सितम्बर 1916 को जन्मे स्व. दीनदयाल की यह बात निःसंदेह भारत के हर प्रश्न के लिए ठीक बैठती है। बहुत सी जगह अपने उत्तरों को खोजने की मेहनत से बचने के लिए हमने विदेशी या पाश्चात्य विचारों या तौर-तरीकों का अनुसरण किया है। इस अंधे अनुसरण में सबसे बड़ी भूल जो हमने की, वह थी विदेशी भाषा में शिक्षा का प्रचार-प्रसार। श्री उपाध्याय का मानना था कि भारत एवं भारतीयता तब तक ही रहेगी जब तक भारतीय भाषाएं रहेंगी। 14 सितम्बर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष पुनः हिन्दी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर यह आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाएं एवं बोलियां केवल दिवस के रूप में ही मनाने के लिए रह गई हैं? क्या शिक्षा जगत में भाषा के रूप में जो सम्मान हमारी भाषाओं को दिया जाना चाहिए था, वह उन्हें मिल पाया है?

यदि कोई चीज श्रेष्ठ हो अथवा उससे मनुष्य एवं राष्ट्र के विकास को गति मिलती हो तो उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में अपनाने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसको शिक्षा का माध्यम बनाना एक राष्ट्रीय आपदा है। पर क्या शिक्षा जगत में अंग्रेजी की प्रभुता और उसकी भक्ति ने भारत को, भारतीय शिक्षा जगत को, भारतीय छात्र को या भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में काई योगदान दिया है? इन प्रश्नों के गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। इस विषय पर बात प्रारंभ करने से पहले, भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति और भारत को विज्ञान और मिसाइल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाले डा. एपीजे अब्दुल कलाम के एक वाक्य को बताना आवश्यक है। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा उनके मौलिक और सकारात्मक होने के बारे में प्रश्न किया था। उत्तर में डा. कलाम ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता के कारण ही वह किसी कुंठा का शिकार नहीं हुए और यही उनकी मौलिकता एवं सकारात्मकता का रहस्य है।

भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी के जाल में फंसाकर और पीढ़ी दर पीढ़ी छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा न देकर कहीं हमने बहुत से अब्दुल कलाम जैसी प्रतिभाओं का दम तो नहीं घोंटा? भारत का जितना मूल विचार या मूल काम हम बोलते हैं या जिसकी चर्चा विश्व भर में करते हैं, वह सब के सब भारतीय भाषाओं में है। सब जानते हैं मैकाले द्वारा एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी को भारत के ऊपर थोपा गया, जिससे भारत की मूल शिक्षा का नाश तो हुआ ही, साथ ही भारत शिक्षा या ज्ञान क्षेत्र में विश्व को कुछ नया नहीं दे पाया। देता भी कैसे? जिस भाषा में भारतीय छात्र सोचता, पलता-बढ़ता है, वह भाषा तो शिक्षा में उसे कहीं मिली ही नहीं। जिस कारण भारतीय छात्र ने कुछ नया या सृजनात्मक करने के बजाए अपना आधे से ज्यादा विद्यार्थी जीवन शिक्षा के माध्यम की भाषा सीखने में ही लगा दिया। उदाहरण के लिए जो बच्चा घरेलू भाषा में पिता का नाम पूछे जाने पर तुरंत बताता है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के कारण उसे महीनों इसी बात का रट्टा लगाना पड़ता है। पिता का नाम अंग्रेजी में बताने की प्रक्रिया को रट-रट कर भी वह उस आत्मविश्वास से बता नहीं पाता।

यह एक बहुत प्रारंभिक और छोटा सा उदाहरण है। इसी उदाहरण से हम कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेजी या विदेशी भाषा में शिक्षा किस प्रकार हमारे आत्मविश्वास और सृजनात्मकता को मारती है। विदेशी भाषा को सीखने और रटने में ही विद्यार्थी का आधा जीवन चला जाता है, तो हम किस तरह से भारतीय छात्र से शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कुछ मौलिक और सृजनात्मक काम की अपेक्षा कर सकते हैं। हमें आकलन करना चाहिए कि क्या अंग्रेजी शिक्षा या उसके माध्यम से परोसी जा रही शिक्षा से आज एक भी मौलिक काम हम विश्व को बता सकते हैं। आज भी जिन साहित्यों या शोध कार्यों पर हम गर्व करते हैं, वह सब भारतीय भाषाओं में ही है। विदेशी भाषा में शिक्षा ने हमारी रचनात्मकता को खत्म कर दिया है। जिस भाषा में हम सोचते हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि अकादमिक जगत में उसकी स्वीकार्यता नहीं है।

विदेशी भाषा में शिक्षा न केवल विद्यार्थी में सृजनात्मकता या रचनात्मकता का विकास होने से रोक रही है, अपितु अपनी संस्कृति, भाषा और लोक के प्रति हीन भाव भी पैदा कर रही है। भाषा यदि केवल संचार का माध्यम हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वह एक संस्कृति, सभ्यता, उसके तौर-तरीकों, पहचान और सोच को भी आगे प्रवाहित करती है। वह केवल संचार का माध्यम भर नहीं है। भारतीय छात्र से भारतीयता को दूर करने में यदि सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो वह अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का है, ऐसी भाषा जिसकी शिक्षा, व्याकरण, साहित्य आदि में कहीं भारत की झलक ही नहीं मिलती।

एक और हानि जो अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय छात्र समाज की है वह यह कि इसने छात्रों को श्रेष्ठ और हीन के दो गुटों में बांट दिया। जिन छात्रों की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है वह बाजार के सहयोग से स्वघोषित श्रेष्ठ बन गए और भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पिछड़े की श्रेणी में खुद को पाता है। शहरों में भाषा को लेकर समाज का दृष्टिकोण भी ऐसा ही हो गया है, जिस कारण अंग्रेजी की ठीक जानकारी न होने के कारण भारत का एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग अपने आप को अंग्रेजी के बाजार में लाचार पाता है और अपनी शिक्षा और भाषा को दोयम दर्जे का मानने पर मजबूर हो जाता है।

स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, रबीन्द्रनाथ टैगोर, डा. बी.आर आम्बेडकर, महात्मा गांधी सरीखे सैंकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं, जो कि विदेशी भाषाओं की अच्छी जानकारी रखते थे और इनमें से कईं तो एक से अधिक विदेशी भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। लेकिन इन सब ने शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त की और अपना मूल काम अपनी मातृभाषा में ही किया।

इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि समाज विज्ञान में जिस समाज की हम पढ़ाई कर रहे हैं वो उसकी भाषा में ही नहीं है। फिर इसी शिक्षा द्वारा हम उसी समाज के उत्थान के लिए जो शोध करते हैं या कुछ सुझाव देते हैं, वह भी उसकी भाषा में नहीं होता। तो प्रश्न यह उठता यह कैसी समाज विज्ञान की शिक्षा जिसका उस समाज और उसकी भाषा से कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसी शिक्षा से न तो छात्रों का कुछ भला हो रहा है और न ही समाज का। इस शिक्षा से हमें कुछ मिल रहा है तो वह है अपने अस्तित्व और अपनी पहचान से विमुख निराश छात्रों की बड़ी फौज, जिसे यह नहीं पता चल पा रहा कि उसने इतने वर्ष पढ़ा क्या और उसका समाज को या उसको लाभ क्या मिला?

यहां विरोध किसी भाषा का नहीं है, न ही विदेशी भाषा सीखने में कोई ऐतराज है। बात सिर्फ शिक्षा में भाषा को लेकर है, जिसने भारतीय छात्र को कुछ मूल करने का, कुछ सृजनात्मक करने का अवसर ही नहीं दिया। जब आम व्यवहार, लोक व्यवहार, सामान्य समाज विज्ञान, लोक कला एवं संस्कृति, मूल विज्ञान एवं साहित्य, आदि को विद्यार्थी अपनी भाषा में अच्छे से पढ़ और समझ ले, तो उसके बाद विदेशी भाषा को पढ़ने और सीखने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर छात्रों के विकास और सृजनात्मकता को कुचलना ठीक नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, रबीन्द्रनाथ टैगोर, डा. बी.आर आम्बेडकर, महात्मा गांधी सरीखे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं, जो कि विदेशी भाषाओं की अच्छी जानकारी रखते थे और इनमें से कई तो एक से अधिक विदेशी भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। लेकिन इन सब ने शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त की और अपना मूल काम अपनी मातृभाषा में ही किया। उदाहरण के लिए भारत में सामाजिक समानता, एकता और बंधुता की लड़ाई लड़ने वाले डा. आम्बेडकर की सारी उच्च शिक्षा अमेरिका एवं ब्रिटेन में हुई। विदेश से डाक्टरेट और स्नात्कोत्तर की दो-दो डिग्रियां लेने के बाद जब वह भारत में आते हैं, तो 1920 में अपना समाचार पत्र 'मूकनायक' मराठी भाषा में शुरु करते हैं न कि अंग्रेजी में।

इन सबके उदाहरण से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यदि हम अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करते हैं तो हमें विदेशी भाषा सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहां तो संकट यह खड़ा हो गया है कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने में पहले 15 से 20 वर्ष उस भाषा को सीखने में ही चले जाते हैं और उसके बाद न तो अपनी मातृभाषा ठीक से आती है और न ही अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा और छात्रों के उत्थान के लिए इस समस्या को सुलझाना जरूरी है और उत्तर भारत से ही ढूंढने होंगे। ■

नागालैंड में पहली बार हुआ अभाविप का अभ्यास वर्ग, बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता

नागालैंड की राजधानी कोहिमा के एसआईआरडी परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा पहली बार अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य के छात्र - छात्राओं ने भाग लिया और परिषद् की कार्यपद्धति को निकट से जाना। अभ्यास वर्ग में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे राष्ट्रीय माध्यमिक शैक्षिक अभियान, नागालैंड के निदेशक विसिजोले यशु ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् बेहद अनुशासित छात्र संगठन है। उन्होंने उपस्थित छात्र - छात्राओं को परिषद् से जुड़कर अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया। वहीं अभाविप के अखिल भारतीय आयाम प्रमुख नागराज रेड्डी ने वर्तमान परिदृश्य एवं हमारी भूमिका विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, इस अभियान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चिंतन करना चाहिए। परिषद् आरंभ से ही राष्ट्र को केन्द्रबिंदु मानकर कार्य कर रही है। श्री रेड्डी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद् केवल परिसर में कार्य करने वाला छात्र संगठन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रखर प्रहरी भी है। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जोराम आनिया ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अभाविप की भूमिका के बारे में प्रकाश डाला, जैकप लुखम ने परिषद् का इतिहास और शैक्षिक संकल्पना पर अपना मत रखा। अभ्यास वर्ग के दूसरे व अंतिम दिन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नीरव घेलानी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद् के प्रकल्प SEIL के माध्यम से पूर्वोत्तर के छात्रों को शेष भारत को जानने का मौका मिला वहीं शेष भारत के लोगों को पूर्वोत्तर की परंपराओं को जानने व समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सील के माध्यम से पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच आत्मीयता का संचार हुआ। परिषद् एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है जो शैक्षिक परिसर में 365 दिन सक्रिय रहकर छात्रों की समस्याओं के निदान हेतु संघर्ष करता है। देश में कोई भी विपदा आती है तो परिषद् के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा में जुट जाते हैं। परिषद् एक संगठन नहीं अपितु व्यक्तित्व निर्माण की

पाठशाला है, आप सभी से आग्रह है कि परिषद् के साथ जुड़कर राष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित करें ताकि भारत अपने पुराने वैभव को एक बार फिर से प्राप्त कर सके। इस मौके पर सील प्रतिभागियों ने अपने - अपने सील यात्रा के अनुभवों को साझा किया, खुत्सुलु डोजो के संस्मरण को सुनकर उपस्थित कार्यकर्ता भावुक हो उठे। वर्ग में तीन जिलों के 12 महाविद्यालयों से लगभग तीन दर्जन कार्यकर्ता उपस्थित थे जिसमें आठ छात्रा कार्यकर्ता, पांच शिक्षक शामिल हैं। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का सितम्बर 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

ABVP expresses deep concerns over nefarious activities in Educational Institutions.

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad expressed deep concern over the revelations made by Maharashtra ADG Param Bir Singh in his press conference held in Pune.The exposer brings to fore the incriminating evidences against urban naxals posing as prominent civil society members. Their malicious intentions to influence students from eminent institutions such as TISS and JNU to join them in their nefarious activities are alarming and condemnable. It is pertinent to note that, as mentioned in the letter written by Comrade Prakash to Comrade Surendra dated 25 September 2017, these Breaking India forces have all the intentions to recruit students from prestigious universities like JNU, DU and BHU to indulge in creating a sense of paranoia by building false narrative. In the prevalent conditions, ABVP appeals to the student community to be aware of the real face behind such 'public intellectuals' who hatch conspiracies to create unrest in society. We urge students to refrain from these influences and give them a befitting reply. From the letters seized by police in the aftermath of Bhima-Koregaon violence perpetrated by anti-social elements like Elgar Parishad. It is evident that the people who are put under arrest, some of whom were convicted in the erstwhile UPA regime, pose a grave threat to nation's security and integrity. ABVP appeals to the Government of India to conduct thorough and unbiased investigation and to not reel under the pressure by certain fake groups pretending to be legitimate civil society representatives. ■

केरल में बजा अभाविप का डंका, छात्रसंघ की सभी सीटों पर जीत

केरल के कासरकोड जिले में सम्पन्न छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने तीन महाविद्यालयों के सभी 32 सीटों पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। देश में बढती राष्ट्रवाद की बहस के लिए यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। केरल जैसे प्रदेश जिसे वामपंथ विचारधारा के लोग अपना गढ मानते है, जहां पर अभाविप, रा. स्व. संघ एवं उनसे संबंद्ध संगठनों के कार्याकर्ताओं की हत्या आम बात है। ऐसे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद् की जीत काफी अहम मानी जा रही है। कोई भी जीत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सरकार के मुखिया के गढ़ में हासिल की गई हो। केरल के प्रदेश मंत्री श्याम राज की मानें तो सरकार के मुखिया का प्रश्रय पाकर पाकर वामपंथ से प्रेरित संगठन अभाविप के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, कार्यकर्ताओं की आवाज को उठने के पहले ही दबा दी जाती है, वैसे जगहों पर परिषद् के कार्यकर्ताओं पर छात्रों का विश्वास हमारे लिए गौरव की बात है। केरल में अभाविप एवं राष्ट्रीय विचारों की बढ़ती लोकप्रियता से वामपंथी घबरा चुके हैं, इन्हें डर है कि कहीं देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां से भी उनकी बोरिया बिस्तर समटा न जाये, इसलिए उनलोगों के द्वारा लोगों को डराया - धमाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के छात्र एवं युवा को यह आभास हो गया है कि छात्रहित की बात करने वाला, विपदा में हर कदम पर सहयोग करने वाला, राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार करने वाला अगर कोई छात्र संगठन है तो वह है अभाविप....। यह जीत परिषद् के शहीद हुए कार्यकर्ताओं को समर्पित हैं जिन्होंने राष्ट्रीय विचार के लिए वामपंथी हिंसा में अपने प्राणों को गंवा दिया। ■

देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना कितना सही?

पिछले कुछ दिनों से इस बात पर देश भर में चर्चा हो रही है कि क्यों न लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाये। केंद्र सरकार खुल कर आम चुनाव एक साथ कराने की वकालत कर रही है, जबकि बाकी राजनीतिक पार्टियों में निर्णय ना लेने की स्थिति या यूँ कहें कि उहापोह की स्थिति बरक़रार है। कांग्रेस ने विधि आयोग के समक्ष इस विषय पर अपनी असहमति स्पष्ट रूप से जता दी है तथा इसे भारतीय संघवाद के विरुद्ध बताया है। वहीं एक साथ चुनाव कराने के मसले पर बीजेपी को तेलंगाना राष्ट्र समिति(टीआरएस) का साथ मिला है। आजादी के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि, इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, लेकिन सुविधा के नाते 1952 के पहले आम चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए थे, तकरीबन 15 साल तक विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ चले लेकिन बाद में कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कुछ सरकारें अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले गिर गईं। अब एक बार फिर से दोनों चुनाव एक साथ कराने की बात चल रही है। एक साथ चुनाव कराने से जहां एक ओर पैसे का खर्च कम होगा वहीं दूसरी ओर सरकारी मशीनरियों जैसे सेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती जैसे मसले से भी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 'एक देश – एक चुनाव' की धारणा देश के संघात्मक ढ़ांचे के विपरीत सिद्ध हो सकती है। एक साथ चुनाव कराने में संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव सम्पन्न कराना पदाधिकारियों की नियुक्ति, ई.वी.एम. की आवश्यकताओं व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से एक कठिन कार्य है। विधि आयोग ने भी अपनी मसौदा रिपोर्ट में कहा है कि ईवीएम मशीन, पेपर ट्रोल मशीनों को खरीदने के लिए कम से कम 4555 करोड़ रुपये की जरुरत होगी। 'एक देश – एक चुनाव' के मुद्दे पर आम जनमानस की राय को जानने के लिए 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बात की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश –

एक साथ चुनाव कराना कल्पना की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मूल भावना को ध्यान में रखकर यह अव्यावहारिक है। संविधान में यह कहीं नहीं कहा गया है कि केंद्र और राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते, लेकिन कानून का सहारा लेकर राज्यों को इसके लिये बाध्य करना संघवाद की भावना से भी ठीक नहीं होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा। छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम हो जाएगी क्योंकि बड़े राजनीतिक नेताओं और पार्टियों से जुड़ा प्रभामंडल राज्य चुनावों के परिणाम को प्रभावित करता है। अलग-अलग चुनाव कराने में मतदाताओं को आसानी रहती है और वे यह अंतर करने में सक्षम होते हैं कि कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिये ठीक है और कौन सी पार्टी राज्य में बेहतर शासन दे पाएगी।

- **योगिता,** शिक्षिका, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली

किसी भी लोकतंत्र में इस तरह लगातार चुनाव नहीं होते, जैसे हमारे देश में होते हैं । एक साथ चुनाव करवाने का विचार उचित है, लेकिन भारत जैसे देश में तुरंत लागू हो पाना संभव नहीं लगता। स्थानीय भावनाओं तथा विचारों को पूरी जगह मिलनी चाहिए, बार-बार चुनाव करवाने में समय, पैसे तथा ऊर्जा की बर्बादी है, लेकिन इस विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र को सुरक्षित तथा जनता को संतुष्ट रखने के लिए यह बड़ी कीमत नहीं है।

- **नितिनेंद्र प्रताप सिंह,** योग प्रशिक्षु, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चुनाव एक साथ होने से वोटर्स का उत्साह बरकरार रहेगा और इससे राजनैतिक पार्टियों का पैसा और समय दोनों ही बचेगा। इसके अलावा आचार संहिता भी एक बार ही लागू होगी जिससे सरकारें भी अपने कार्यों को निर्बाध गति से करने में समर्थ होंगी । एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जिसके चलते अनुच्छेद 83, 172, 85 और 174 में बदलाव करने होंगे। कुछ व्यवहारिक दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो ये फ़ैसला देशहित में रहेगा।

- **मीनाक्षी राय,** प्रतियोगी छात्रा, नेवादा, बिहार

मेरे हिसाब से एक देश एक चुनाव होना सही है क्योंकि चुनाव के चक्कर में पैसे की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। आये दिन कहीं ना कहीं चुनाव की ख़बर सुनाई देती है । पैसे को पानी को तरह बहाया जाता है, कभी कभी लोकसभा से ज्यादा पैसा विधानसभा लड़ने वाले व्यक्ति बहा देते हैं। चुनाव आयोग को देश के सामने एक व्यावहारिक प्रक्रिया के तहत आम चुनाव करवाने चाहिए, इससे देश का समय और धन दोनों बचेगा और चुनी गई सरकार अपने घोषणापत्र को सही रूप से बिना आचारसंहिता के डर के लागू कर सकेगी।

- **सारंग जायसवाल,** प्रतियोगी छात्र, पुणे, महाराष्ट्र

जब भी चुनाव होते हैं, तो नीति निर्माण की प्रक्रिया और सामाजिक माहौल बिगड़ जाता है। एक साथ चुनाव होने से इस समस्या पर अंकुश लग सकेगा। बार-बार चुनाव का सामना करने वाली सरकारें दीर्घकालीन के बजाय अल्पकालीन मुद्दों पर ही अधिक ध्यान देती हैं। चुनाव अभियान के दौरान धर्म, जाति, उपजाति तथा अन्य विभाजनकारी ताकतें मज़बूत होती हैं। एक साथ लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव कराए जाएँ तो धन और समय दोनों की बचत होगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा।। ऐसे में इस प्रक्रिया को सरल एवं कम खर्चीली बनाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि जब सभी राजनीतिक दलों में सहमति बन जाए, उसके बाद लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएँ। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी।

- **राम प्रकाश यादव,** शिक्षा सहायक, राष्ट्रपति भवन

परिषद् गतिविधियाँ

सांविष्कार लाइव, भोपाल द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री के. एन. रखुनंदन व अन्य

केरल के (कासरकोड जिला) महाविद्यालयीन छात्रसंघ चुनाव में एकतरफा जीत के बाद विजय जुलूस निकालते अभाविप कार्यकर्ता

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 Septmeber, 2018
Date of Publishing: 8 September, 2018

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

छात्र अधिकार रैली